THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) and (b) On the basis of performance of Central Public Sector Undertakings during 1991-92, 50 sick PSUs are referable to BIFR. A list of such enterprises is annexed statement. *(see* below)

(c) The Country Economic Memorandum of World Bank, dated 18th May, 1992 did not make any such suggestion.

(d) Does not arise.

(e) In order to protect the welfare of the affected workers of those enterprises which have been registered with BIFR for formulation of revival/rehabilitation plants, a National Renewal Fund has been created as a safety net.

Statement

List of PSUs referable to BIFR

1. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
2. Bengal Immunity Ltd.
3. Bharat Brakes & Valves Ltd.
4. Bharat Gold Mines Ltd.
5. Bharat Ophtahlmic Glass Ltd.
6. Bharat Process & Mechanical Engineers Ltd.
7. Bharat Pumps & Compressors Ltd.
8. Bharat Refractories Ltd.
9. Biecco Lawrie Ltd.
10. Birds, Jute & Exports Ltd.
11. Braithwaite & Co. Ltd.
12. British India Corpn. Ltd.
13. Brushware Ltd.
14. Cawnpore Textiles Ltd.
15. Cycle Corporation of India Ltd.
16. Elgin Mills Company Ltd.
17. Fertilizer Corpn, of India Ltd.
18. Heavy Engineering Corpn. Ltd.
19. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd.
20. Hooghly Dock & Port Engineers Ltd.
21. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
22. Indian Firebricks & Insulation Co. Ltd.
23. Mandya National Paper Mills Ltd
24. Mica Trading Corpn, of India Ltd
25. Mining & Allied Machinery Co. Ltd.
26. Nagaland Pulp & Paper Company Ltd.
27. National Bicycle Corporation of India Ltd.
28. National Instruments Ltd.
29. National Jute Manufacturers Co. Ltd.
30. North Eastern Regional Agricultural Mktg. Corpn. Ltd.
31. NTC (A. Pradesh, Karnataka, Kerala & Maha) Ltd.
32. NTC (Gujarat) Ltd.
33. NTC (Madhya Pradesh) Ltd.
34. NTC (Maharashtra North) Ltd.
35. NTC (South Maharashtra) Ltd.
36. NTC (Uttar Pradesh) Ltd.
37. NTC (West Bengal, Assam, Bihar & Orissa) Ltd.
38. Orissa Drugs & "Pharmaceuticals Ltd.
39. Projeets & Development India Ltd.
40. Rehabilitation Industries Ltd.
41. Reyrolle Burn Ltd.
42. Richardson & Cruddas (1972) Ltd.
43. Scooters India Ltd.
44. Smith Stanistreet & Pharmaceuticals Ltd.
45. Tannery & Footwear Corpn, of India Ltd.
46. Triveni Structurals Ltd.
47. Tyre Corporation of India Ltd.
48. U.P. Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
49. Vignyan Industries Ltd.
50. Weighbird (India) Ltd.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन प्रौद्योगिकी का उन्नयन

3226. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन के सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ;

(ख) इनके फलस्वरूप किन-किन उपक्रमों को लाभ हुआ है ; और

(ग) इस प्रकार के कदमों से गत वर्ष उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकी समुन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और यह उद्यम विशेष के लिए होती है। प्रौद्योगिकी समुन्नयन के लिए किए गए उपायों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर अधिकाधिक जोर देना,

प्रौद्योगिकी का संस्थागत विकास/उन्नयन, सहयोगी संस्थाओं से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी-सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करना और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के सहयोग से प्रौद्योगिकी का विकास/उन्नयन करना इत्यादि शामिल हैं । चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का कार्यनिष्पादन विभिन्न तत्वों, जैसे संयंत्र और मशीनरी की दशा, बिजली और कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार मांग/क्रय आदेश की स्थिति इत्यादि पर निर्भर करता है इसलिये केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन से प्राप्त किए लाभों की गणना करना आसानी से संभव नहीं है । बहरहाल पिछले तीन वर्षों तक की अवधि की जानकारी उपलब्ध हैं और उसके दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता का उपयोग निम्न प्रकार से है :

विवरण	1991–92 (%)	1990–91 (%)	1989–90 (%)
जिन एककों ने 75% से अधिक क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	56	54	53
जिन एककों ने 50% या उससे अधिक और 75% से कम क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	20	26	23
जिन एककों ने 50% से कम क्षमता का उपयोग दर्ज किया है उनकी प्रतिशतता	24	20	24
कुल	100	100	100

मारुति उद्योग लिमिटेड में अनियमितताएं

3227. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मारुति उद्योग लिमिटेड में कथित अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) अब तक मारुति उद्योग लिमिटेड में कुल कितनी धनराशि का घपला हुआ है तथा इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने जांच के आदेश दे दिये हैं ; यदि नहीं, तो ऐसे आदेशों के कब तक दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

Appointment of Directors in PSUs

3228. SHRI GHUFRAN AZAM:
PROF. SAURIN BHATTACHARAYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state : (a) whether there has been excessive delays in granting approvals of the Government to the appointments of Directors in Public Sector Undertakings ;

(b) whether the selected candidates for the various posts of Board level appointments as were done by the PESB in the first four months of *the* year 1993 are yet to get clearance ;

(c) whether the concerned ministries have been withholding information from the ACC ; and

(d) if so, the facts thereof and steps to be taken to expedite the approvals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Committee on KVIC

3229. SHRI S. MUTHU MANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are planning to set Up a committee to get into the problems being faced by the Khadi and Village Industries ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) how many applications/proposals are pending for clearance from Government to set up projects under this category in Tamil Nadu ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) The Government have already constituted a High Power Committee headed by the Prime Minister with a view to accelerate the growth & development of Khadi & Village industries sector.

(c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.